



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1070]

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 19, 2017/चैत्र 29, 1939

No. 1070]

NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 19, 2017/CHAITRA 29, 1939

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 अप्रैल, 2017

**का.आ. 1210 (अ).-** सेवाओं या फायदों या सहायिकियों के परिदान के लिए एक पहचान दस्तावेज के रूप में आधार का उपयोग सरकारी परिदान प्रक्रियाओं का सरलीकरण करता है, पारदर्शिता और दक्षता लाता है और फायदाग्राहियों को सुविधापूर्वक और निर्बाध रीति में उनकी हकदारियों को सीधे प्राप्त करने में समर्थ बनाता है और आधार किसी व्यक्ति की पहचान को साबित करने के लिए बहुल दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता को समाप्त करता है;

और, भारत सरकार में कारपोरेट कार्य मंत्रालय (जिसे इसके पश्चात् मंत्रालय कहा गया है) वाणिज्य, विधि, अर्थशास्त्र और प्रबंधन पाठ्यक्रमों में पढ़ने वाले स्नातकोत्तर छात्रों को संघ सरकार की कारपोरेट नीतियों के प्रतिपादन और कार्यान्वयन के संबंध में जागरूकता का विकास करने के लिए इंटरनशिप स्कीम (जिसे इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है) को प्रशासित कर रहा है। इस मंत्रालय द्वारा आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं और चयन समिति द्वारा दस इंटर्न (जिसे इसके पश्चात् लाभार्थी कहा गया है) का चयन किया जाता है और इस इंटरनशिप की अवधि अधिकतम दो मास की है और चयन गए इंटर्न को 10000/-रुपये प्रति व्यक्ति प्रतिमाह की मासिक वृत्तिका (जिसे इसके पश्चात् लाभ कहा गया है) संदत्त की जाती है, जिसमें भारत की संचित निधि से आवर्ती व्यय अंतर्बलित है।

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 के उपबंधों के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, निम्नलिखित अधिसूचित को करती है, अर्थात्:-

- (1) इस स्कीम के अधीन लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र किसी व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है कि वह आधार रखने का सबूत प्रस्तुत करे या आधार प्रमाणीकरण प्रक्रिया पूर्ण करे।
- (2) इस स्कीम के अधीन लाभ प्राप्त करने के इच्छुक किसी व्यक्ति, जिसके पास आधार संख्या नहीं है या जिसने अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं किया है, को इंटरनशिप प्रारंभ करने के 30 दिनों के भीतर आधार नामांकन के लिए आवेदन करना अपेक्षित है। यदि वह आधार अधिनियम की धारा 3 के अनुसार आधार प्राप्त करने का हकदार नहीं है तो

ऐसे लाभार्थियों को आधार के लिए नामांकन करवाने हेतु किसी आधार नामांकन केन्द्र ([www.uidai.gov.in](http://www.uidai.gov.in) पर सूची उपलब्ध है) पर जा सकते हैं।

(3) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार, मंत्रालय, जो किसी व्यक्ति से आधार प्रस्तुत करने की अपेक्षा करता है, द्वारा ऐसे हिताधिकारियों के लिए आधार नामांकन सुविधाएं देना अपेक्षित है जिन्होंने अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं कराया है और यदि आसपास जैसे कि ब्लॉक, या तालुका या तहसील में कोई आधार नामांकन केन्द्र नहीं है, तो मंत्रालय से अपेक्षा की जाती है कि वह यूआईडीएआई के वर्तमान रजिस्ट्रार के समन्वय से सुविधाजनक अवस्थानों पर नामांकन सुविधा उपलब्ध कराए या मंत्रालय स्वयं यूआईडीएआई रजिस्ट्रार बनकर आधार नामांकन सुविधाएं दे:

परंतु कि, व्यक्ति को आधार दिए जाने के समय तक स्कीम के अधीन फायदे निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने के अध्यक्षीन ऐसे व्यक्तियों को इस स्कीम के अधीन फायदे दिए जाएंगे, अर्थात्:-

(क) (i) यदि उसने नामांकन करा लिया है तो उसकी आधार नामांकन आईडी स्लिप; या

(ii) पैरा 2 के उप-पैरा (2) में यथाविनिर्दिष्ट अनुसार आधार नामांकन के लिए उसके द्वारा किए गए अनुरोध की प्रति; और

(ख) निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज -

(i) भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किया गया मतदाता पहचान पत्र; या

(ii) स्थायी खाता संख्या (पैन) कार्ड; या

(iii) पासपोर्ट; या

(iv) राशन कार्ड;

(v) फोटो सहित बैंक या पोस्टऑफिस पासबुक;

(vi) पहचान का प्रमाण पत्र जिस पर उस व्यक्ति का फोटो हो और जो किसी राजपत्रित अधिकारी या किसी तहसीलदार द्वारा शासकीय पत्र शीर्ष पर जारी किया गया हो; या

(vii) मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के अधीन अनुज्ञप्ति अधिकारी द्वारा जारी किया गया चालान अनुज्ञप्ति; या

(viii) किसान फोटो पासबुक; या

(ix) मंत्रालय द्वारा यथा विनिर्दिष्ट अन्य कोई दस्तावेज।

परंतु यह और भी कि उपर्युक्त दस्तावेजों की जांच इस मंत्रालय द्वारा इस प्रयोजनार्थ विनिर्दिष्ट रूप से पदाभिहित किए गए किसी अधिकारी द्वारा की जाएगी।

2. हिताधिकारियों को इस स्कीम के अधीन सुविधाजनक और निर्बाध फायदे प्रदान करने हेतु, मंत्रालय निम्नलिखित सहित सभी अपेक्षित व्यवस्थाएं करेगा, अर्थात्:-

(क) आवेदकों को इस स्कीम के अधीन फायदे प्राप्त करने के लिए आधार की अपेक्षा के बारे में जागरूक करने हेतु मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार किया जाएगा और व्यक्तियों को सूचनाएं दी जाएंगी और उन्होंने अभी तक नामांकन नहीं करवाया है तो इंटरनेट प्रारंभ होने के 30 दिन के भीतर अपने क्षेत्र में निकटतम नामांकन केन्द्र में स्वयं को नामित करवाने की सलाह दी जाएगी। उन्हें नामांकन केन्द्रों की अवस्थिति की सूची ([www.uidai.gov.in](http://www.uidai.gov.in) पर सूची उपलब्ध है) उपलब्ध कराई जाएगी।

(ख) यदि हिताधिकारी आसपास, जैसे कि ब्लॉक या तालुका या तहसील में, नामांकन केन्द्र नहीं होने के कारण नामांकन करवाने में असमर्थ होते हैं तो, मंत्रालय को सुविधाजनक अवस्थानों पर आधार नामांकन सुविधाएं उपलब्ध करवानी अपेक्षित है और हिताधिकारियों से अनुरोध है कि पैरा 1 के उप-पैरा (3) के परंतुक में यथा विनिर्दिष्ट अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर और अन्य ब्यौरे देकर नियोजक या प्रशिक्षण संस्थान के संबंधित पदाधिकारियों या इस प्रयोजन के लिए वेब पोर्टल के माध्यम से आधार नामांकन के लिए अपना आवेदन रजिस्टर करें।

3. यह अधिसूचना असम, मेघालय और जम्मू-कश्मीर राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।

[फा.सं.आई-34011/23/2016-समन्वय]

ए. अशोली चलाई, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

### NOTIFICATION

New Delhi, the 5th April, 2017

**S.O.1210(E).**—Whereas, the use of Aadhaar as identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner and Aadhaar obviates the need for producing multiple documents to prove one's identity;

And whereas, the Ministry of Corporate Affairs (hereinafter referred to as the Ministry) in the Government of India is administering the Internship Scheme (hereinafter referred to as the Scheme) to provide a platform for post-graduate students who are pursuing courses in Commerce, Law, Economics and Management streams to develop awareness about formulation and implementation of corporate policies of the Union Government. Applications are invited by the Ministry and ten interns (hereinafter referred to as the beneficiaries) are selected by the Selection Committee and the internship is for a maximum duration of two months and the interns selected are paid a monthly stipend of Rs.10,000/- per person per month (hereinafter referred to as benefits), which involves recurring expenditure from the Consolidated Fund of India.

Now, therefore, in pursuance of the provisions of the section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby notifies the following, namely: --

1. (1) An individual eligible for availing benefit under the Scheme is hereby required to furnish proof of possession of Aadhaar or undergo Aadhaar authentication.
- (2) Any individual desirous of availing benefit under the Scheme, who does not possess the Aadhaar number, or, has not yet enrolled for Aadhaar, is hereby required to make application for Aadhaar enrolment within 30 days of joining the internship. In case he or she is entitled to obtain Aadhaar as per section 3 of the Aadhaar Act and such individuals may visit any Aadhaar enrolment centre (list available at [www.uidai.gov.in](http://www.uidai.gov.in)) to get enrolled for Aadhaar.
- (3) As per regulation 12 of Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the Ministry which requires an individual to furnish Aadhaar, is required to offer Aadhaar enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in the vicinity such as in the Block or Taluka or Tehsil, the Ministry is required to provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of UIDAI or by Ministry itself becoming UIDAI Registrar:

Provided that till the time Aadhaar is assigned to the individual, benefits under the Scheme shall be given to such individuals subject to the production of the following documents, namely:-

- (a) (i). If he or she has enrolled, his or her Aadhaar Enrolment ID slip; or
- (ii). a copy of his or her request made for Aadhaar enrolment, as specified in sub-paragraph (2) of Paragraph 2; and
- (b) Any one of the following documents:-
  - (i) Voter Identity Card issued by the Election Commission of India; or
  - (ii) Permanent Account Number (PAN) Card; or
  - (iii) Passport; or

- (iv) Ration Card or
- (v) Bank or Post Office Passbook with photo;
- (vi) Certificate of Identity having photo issued by the Gazetted officer or Tehsildar on an official letter head; or
- (vii) Driving license issued by the Licensing Authority under the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988); or
- (viii) Kisan Photo Passbook; or
- (ix) Any other document as specified by the Ministry.

Provided further that the above documents shall be checked by an officer specifically designated by the Ministry for that purpose.

2. In order to provide convenient and hassle free benefits to the beneficiaries under the Scheme, the Ministry shall make all required arrangements including the following, namely:-

- (a) Wide publicity through media and individual notices to be given to the applicants to make them aware of the requirement of Aadhaar to receive benefits under the Scheme and they may be advised to get themselves enrolled at the nearest enrolment centre available in their areas within 30 days of joining the internship in case they are not yet enrolled. The list of locality available enrolment centres (list available at [www.uidai.gov.in](http://www.uidai.gov.in)) shall be made available to them.
- (b) In case, beneficiaries are not able to enrol due to non-availability of enrolment centres in the near vicinity such as in the Block or Taluka or Tehsil, the Ministry is required to create Aadhaar enrolment facilities at convenient locations, and the beneficiaries may be requested to register their requests for Aadhaar enrolment by giving their names, addresses, mobile numbers and other details as specified in the proviso to sub-paragraph (3) of paragraph 1, with the concerned officials of the employer or training institute or through the web portal provided for the purpose.

3. This Notification shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette in all States and Union Territories except the States of Assam, Meghalaya and Jammu and Kashmir.

[F. No I-34011/23/2016-Coord]

A. ASHOLI CHALAI, Jt. Secy.